ई संदेश

02 अप्रैल, 2026 | अंक -199

सात दिन, सात पृष्ठ

गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन: युवाओं के स्टार्टअप सपनों को मिली 'प्लग एंड प्ले' की नई उड़ान

ग्लोबल एविएशन के मानचित्र पर चमका उत्तर प्रदेश: जेवर एयरपोर्ट के साथ शुरू हुआ समृद्धि और निवेश का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से सुदृढ़ हुई स्वास्थ्य सेवाएँ: मुख्यमंत्री ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

डिजिटल सशक्तिकरण से संवरेगा प्रदेश का बचपन: मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन

शिक्षा और संबल का नया अध्याय: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 लाख विद्यार्थियों और 33 हजार आश्रित परिवारों के खातों में भेजे 3,450 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की तैयारी: मुख्यमंत्री ने दिए फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश

स्वच्छता और हरित ऊर्जा के संगम से निखरेगी लक्ष्मणपुरी: मुख्यमंत्री ने कूड़ा प्रबंधन हेतु 250 ई-वाहनों को दिखाई हरी झंडी

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उदघाटन: युवाओं के स्टार्टअप सपनों को मिली 'प्लग एंड प्ले' की नई उड़ान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में 26 मार्च 2026 को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में नवनिर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उदघाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यह पार्क युवाओं की सॉफ्ट स्किल को एक नया वैश्विक मंच प्रदान करेगा। लगभग 3.5 एकड़ भूमि पर 20 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह अत्याधुनिक केंद्र 25,000 वर्ग फुट में फैला है, जिसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0) द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है। इस केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका 'प्लग एण्ड प्ले' मॉडल है, जहाँ स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को बिजली, स्थान या अन्य बुनियादी सुविधाओं की चिंता करने के बजाय केवल अपने कंप्यूटर और विचारों के साथ आकर काम शुरू करने की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का सूक्ष्म अवलोकन किया और परिसर में पौधरोपण भी किया। उन्होंने तकनीकी शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि गोरखपुर अब केवल हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी अपनी धमक दिखाएगा। आगामी 15 अप्रैल को क्षेत्र में पहले 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' के शुभारंभ की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी और एम0पी0आई0टी0 जैसे संस्थान इस नई तकनीकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि वासंतीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को इस केंद्र का उदघाटन हुआ है, जो इसके उज्ज्वल भविष्य का संकेत है। उन्होंने अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर होने वाले ऐतिहासिक सूर्य तिलक का उल्लेख करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं।

तकनीक और नवाचार के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुरक्षा और विकास यात्रा पर भी चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के दौर में देश की मजबूती का श्रेय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को देते हुए उन्होंने नागरिकों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और राष्ट्रहित में सरकार के साथ कदम मिलाकर चलने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवश्यक सेवाओं जैसे रसोई गैस की होम डिलीवरी निरंतर जारी रहेगी और लोगों को ईंधन के लिए लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्थापित अत्याधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए उपलब्ध कराई गई 50 करोड़ रुपये की सहायता राशि का भी जिक्र किया, जिसके लिए जापान के साथ तकनीकी सहयोग पर बातचीत चल रही है।

प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति के विकास को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग आधे महिलाओं द्वारा संचालित हैं। गीडा की प्रगति का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि विगत नौ वर्षों में यहाँ का निवेश 30 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जिससे 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। गोरखपुर में एम्स, आयुष विश्वविद्यालय, फर्टिलाइजर कारखाने और लिंक एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं ने जिले की तस्वीर बदल दी है। अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थानीय संस्थानों के साथ मिलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

ग्लोबल एविएशन के मानचित्र पर चमका उत्तर प्रदेश: जेवर एयरपोर्ट के साथ शुरू हुआ समृद्धि और निवेश का नया अध्याय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 28 मार्च, 2026 को जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में 11,200 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट (प्रथम चरण) का उद्घाटन व कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री जी ने विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) सुविधा का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस एयरपोर्ट को 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' की दिशा में एक नया अध्याय बताया और कहा कि यह युवाओं के भविष्य को नई उड़ान देगा। उन्होंने रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश अब देश के सबसे अधिक एयरपोर्ट वाले राज्यों में शामिल हो गया है। यह हवाई अड्डा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ और फरीदाबाद सहित पूरे क्षेत्र के किसानों, लघु उद्योगों और युवाओं के लिए प्रगति के नए अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 160 होने का उल्लेख करते हुए कहा कि 'उड़ान' योजना ने सामान्य नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ और सस्ता बना दिया है। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक संकटों, विशेषकर पश्चिम एशिया के युद्ध और उसके कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत अपनी शक्ति के भरोसे इन संकटों का सामना कर रहा है और सरकार कदम उठा रही है ताकि सामान्य परिवारों पर इसका बोझ न पड़े। उन्होंने पश्चिमी उत्तर

प्रदेश में हाल के समय में हुए विकास कार्यों, जैसे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उदाहरण देते हुए इसे डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का परिणाम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट और यहाँ विकसित हो रहे फ्रेट कॉरिडोर के कारण उत्तर प्रदेश अब दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। किसानों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि गन्ने से निर्मित एथेनॉल के कारण देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और कच्चे तेल पर निर्भरता कम हुई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का नया 'लॉन्च पैड' बनेगा। उन्होंने बताया कि यह एयरपोर्ट न केवल निवेश और व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि व्यापक रोजगार सृजन का माध्यम भी बनेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में एक रनवे के साथ शुरू हुए इस एयरपोर्ट को आगामी वर्षों में पाँच रनवे तक विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने किसानों का विशेष धन्यवाद किया जिन्होंने संवाद और उचित मुआवजे के बाद इस महापरियोजना के लिए 13 हजार एकड़ भूमि उपलब्ध कराई। जेवर एयरपोर्ट को ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ अत्याधुनिक फिनटेक सिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जो प्रदेश को 'बॉटलनेक स्टेट' से 'ब्रेकथ्रू स्टेट' की पहचान दिलाएंगी।

केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब 'उड्डयन प्रदेश' बन चुका है। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को 'एयरोट्रोपोलिस' की संज्ञा दी और बताया कि यह 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी तरह सक्षम है। 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शून्य उत्सर्जन (Zero Emission) के लक्ष्य के साथ संचालित होगा और इसकी वास्तुकला भारतीय विरासत एवं संस्कृति से प्रेरित है। रणनीतिक रूप से यमुना एक्सप्रेस-वे पर स्थित यह एयरपोर्ट सड़क, रेल और मेट्रो के साथ एकीकृत होकर यात्रियों और माल ढुलाई के लिए एक कुशल मल्टी-मोडल परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस गरिमामयी अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित कई वरिष्ठ मंत्री और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से सुदृढ़ हुई स्वास्थ्य सेवाएँ: मुख्यमंत्री ने 665 नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में 29 मार्च, 2026 को आयोजित एक गरिमामय समारोह में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनियुक्त 665 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए संपन्न की जा रही है, जिसके कारण चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान या विधिक हस्तक्षेप नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया कि विगत 09 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने 09 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की हैं, जो राज्य की बदलती अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक शुचिता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2017 से पूर्व की तुलना में आज उत्तर प्रदेश 'बीमारू' राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश की अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' बन चुका है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी राज्य ने तीन गुना वृद्धि दर्ज की है।

नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होते हैं और उनके प्रशिक्षित होने से ही चिकित्सा सेवाएँ सुलभ होती हैं। उन्होंने लोहिया संस्थान की प्रगति की सराहना करते हुए बताया कि 2017 के बाद इस संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई और आज यह 'गामा नाइफ' तथा रोबोटिक सर्जरी जैसे आधुनिक उपचार केंद्रों के रूप में विकसित हो चुका है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल अपराध बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उतनी ही प्रभावी है। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क और सेमीकंडक्टर यूनिट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे प्रदेश अब निवेश के 'बेस्ट डेस्टिनेशन' के रूप में स्थापित हो चुका है।

समारोह में वैश्विक संकटों और पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व की प्रशंसा की, जिसके कारण भारत कठिन समय में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सरकारी प्रयासों जैसे कि 31 बंद पड़े नर्सिंग कॉलेजों को पुनः संचालित करने, साइबर सुरक्षा के लिए हर जिले में थानों की स्थापना और फॉरेंसिक लैब के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से नर्सिंग के क्षेत्र में अधिक संख्या में आने का आह्वान किया और पेशेवरों को मानवीय स्पर्श (Human Touch) के साथ सेवा करने की प्रेरणा दी। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी प्रदेश की बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की सराहना की, जबकि नवनियुक्त अधिकारियों ने पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लिया।

डिजिटल सशक्तिकरण से संवरेगा प्रदेश का बचपन: मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कर्मियों को बांटे नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 मार्च, 2026 को यहां लोक भवन सभागार लखनऊ में 18,440 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के नियुक्ति पत्र तथा 69,804 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण संपन्न किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने कर-कमलों से नव चयनित 05 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं 05 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और 10 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व 05 मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन देकर पूरे प्रदेश में इस वितरण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले 3,170 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों एवं 140 बाल विकास परियोजना कार्यालय भवनों का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए आंगनवाड़ी केंद्र भवन की नवीन डिजाइन का भी विमोचन किया। बच्चों के स्वास्थ्य की सटीक निगरानी के लिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का वितरण किया, जिसके माध्यम से प्रदेश भर में 01 लाख 33 हजार 282 स्टेडियोमीटर, 58 हजार 237 मदर कम चाइल्ड वेइंग स्केल तथा 10 हजार 553 इन्फेंटोमीटर बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कर्मियों को 'यशोदा मइया' की संज्ञा देते हुए कहा कि जिस प्रकार माता यशोदा ने कृष्ण कन्हैया को गढ़ा था, वैसी ही नैतिक जिम्मेदारी इन कर्मियों की देश के भविष्य को तराशने और उसकी नींव मजबूत करने की है।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि डिजिटल सेवा का हब बन गया है और 69 हजार 800 से अधिक कर्मियों को दिए गए ये स्मार्टफोन उनकी कार्य पद्धति में 'स्मार्टनेस' लाएंगे। इसके जरिए रियल टाइम डाटा अपलोड होने से उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार होगा और विभाग के प्रति जनमानस का सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने रेखांकित किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत अब 03 से 05 वर्ष के बच्चों के लिए इन केंद्रों में ही प्री-प्राइमरी स्कूल संचालित किए जाने हैं, जिसके लिए पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे 27 हजार केंद्रों को अब उनके निजी भवन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि नवजात शिशु सुपोषित और माँ स्वस्थ है, तो भारत का भविष्य सशक्त है और पिछले 09 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने इस दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कोरोना काल के दौरान आंगनवाड़ी और आशा वर्करों द्वारा घर-घर जाकर की गई स्क्रीनिंग के जज्बे को याद करते हुए उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स बताया, जिनके कारण ही प्रदेश इतनी बड़ी आबादी के बावजूद महामारी पर प्रभावी नियंत्रण पा सका।

मुख्यमंत्री ने गौरव के साथ बताया कि 'सम्भव' अभियान के तहत 1.70 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें से 80 प्रतिशत कुपोषित बच्चे अब सुपोषित हो चुके हैं और प्रदेश में स्टंटिंग की दर 48 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को रेसिपी बेस्ड अनुपूरक पुष्टाहार देने वाला देश का प्रथम राज्य बताते हुए कहा कि फेस रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। इस वर्ष 05 हजार कार्यकत्रियों और 60 हजार सहायिकाओं की नई नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा योजनाओं और आयुष्मान भारत के 05 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों को 'सक्षम केंद्र' के रूप में विकसित करने के लिए वहां एल0ई0डी0 टीवी, आर0ओ0 वॉटर और न्यूट्रिशन गार्डन जैसी सुविधाएं देने तथा कर्मियों के मानदेय को 'स्मार्ट' बनाने के लिए नया प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कर्मचारियों के शोषण को रोकने के लिए नवगठित कॉरपोरेशन की व्यवस्था को 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की, ताकि प्रदेश के विकास में भागीदार बनने वाले हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और अधिकार मिल सके। कार्यक्रम में महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी इन उपलब्धियों को बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया।

शिक्षा और संबल का नया अध्याय: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 लाख विद्यार्थियों और 33 हजार आश्रित परिवारों के खातों में भेजे 3,450 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 मार्च, 2026 को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के वंचित और कमजोर वर्ग के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कक्षा-9, कक्षा-10 और दशमोत्तर कक्षाओं के 27,99,982 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में 3,350 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि सीधे हस्तांतरित की। साथ ही, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन 33,334 आश्रित परिवारों को 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की, जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता को खो दिया था। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान स्वयं छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाण-पत्र और पात्र परिवारों को भुगतान प्रमाण-पत्र सौंपकर उनका उत्साहवर्धन किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता और केवल परिश्रमी व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि यह स्कॉलरशिप विद्यार्थियों की मंजिल नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम को संबल प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए स्वयं को तैयार कर सकें।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों को साझा करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कुल 67 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई गई है, जिस पर लगभग 4,800 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र को सरकार की कार्यप्रणाली का आधार बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य वर्ग के गरीबों और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। पिछली सरकारों की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2016-17 में तत्कालीन सरकार ने दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा अन्य कार्यों में डाइवर्ट कर दिया था, जिसे 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद ब्याज समेत छात्रों को लौटाया गया। मुख्यमंत्री ने तकनीक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पहले छात्रवृत्ति वितरण में भारी भ्रष्टाचार था और छात्रों के हाथ में स्वीकृत राशि का आधा हिस्सा भी नहीं पहुंच पाता था, लेकिन आज 'एक क्लिक' की पारदर्शिता ने बिचौलियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

प्रदेश में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त था, चाहे वह कुपोषित बच्चों का पोषाहार हो या निराश्रित पेंशन। उन्होंने गौरव के साथ बताया कि वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सालाना 12 हजार रुपये की पेंशन बिना किसी कटौती के सीधे उनके खातों में मिल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि अब तक 5.54 लाख बेटियों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है, जिसमें प्रति विवाह सरकार 1 लाख रुपये व्यय कर रही है। युवाओं के करियर के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने 'मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग' योजना को और अधिक विस्तार देने की बात कही। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि इस योजना को यूपीएससी, नीट, एनडीए और जेईई जैसी परीक्षाओं के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया जाए और सफल अधिकारियों को प्रतिदिन एक घंटा युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

महिला सशक्तिकरण और डिजिटल उद्यमिता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 8,000 न्याय पंचायतों में डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए है। सरकार इन उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का लक्ष्य है, जिनमें से 50 लाख को पहले ही लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने अंत में विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में संवैधानिक संस्थाओं और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का अपमान किया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने महापुरुषों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर दंगामुक्त और कर्फ्यूमुक्त हो चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। इस समारोह में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और अन्य मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को डिजिटल क्रांति से जोड़ने की तैयारी: मुख्यमंत्री ने दिए फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। 01 अप्रैल, 2026 को लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कृषि विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की और स्पष्ट किया कि सभी किसानों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस डिजिटल पहल को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में यथाशीघ्र विशेष शिविर आयोजित करने पर बल दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा सके और कोई भी पात्र किसान सरकारी व्यवस्थाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। मुख्यमंत्री जी ने दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि राज्य सरकार फार्मर रजिस्ट्री को कृषि क्षेत्र में एक एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित कर रही है, इसके अन्तर्गत कृषि विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की सभी लाभार्थीपरक योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसान को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही पहचान के आधार पर सरल और व्यवस्थित तरीके से प्राप्त हो सके। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं में यदि लाभार्थियों के नाम या अभिलेखों में कोई त्रुटि अथवा विसंगति है, तो उसे आधार से लिंक कर प्राथमिकता के आधार पर संशोधित किया जाए। प्रत्येक पात्र किसान का किसान पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे योजनाओं के लाभ वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए और पात्रता का सत्यापन सुगम हो सके। कृषि विभाग अपनी सभी योजनाओं को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था निर्धारित समय सीमा में तैयार करे और विभागीय पोर्टल को 01 मई, 2026 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाए। इसके माध्यम से लाभार्थियों के चयन और लाभ वितरण की प्रक्रिया को डिजिटल एवं एकीकृत रूप में संचालित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता एवं लघु सिंचाई जैसे सहयोगी विभाग भी अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र के उपयोग के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें और 31 मई, 2026 तक आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें, ताकि सभी विभागों में एक समान व्यवस्था लागू हो सके। उन्होंने विश्वास जताया कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी और लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक जटिलताएं समाप्त होंगी। इससे संसाधनों का लक्षित उपयोग सम्भव होगा तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यक कृषि इनपुट का वितरण अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के लागू होने से योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से किसानों तक पहुंचेगा और एक ही लाभार्थी को बार-बार लाभ मिलने की स्थिति की समीक्षा भी सहज रूप से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि इस कार्य को गम्भीरता से लेते हुए समय सीमा के भीतर पूर्ण करें और इसकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।

स्वच्छता और हरित ऊर्जा के संगम से निखरेगी लक्ष्मणपुरी: मुख्यमंत्री ने कूड़ा प्रबंधन हेतु 250 ई-वाहनों को दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 01 अप्रैल, 2026 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने के संकल्प के साथ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन तथा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा से संचालित 250 इलेक्ट्रिक एवं सी0एन0जी0 वाहनों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित गरिमामयी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने हर्ष व्यक्त किया कि नवनिर्माण के 09 वर्षों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में लखनऊ नगर निगम ने पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री जी ने इस सफलता का श्रेय डबल इंजन सरकार के ठोस प्रयासों तथा कूड़ा-कचरा के वैज्ञानिक प्रबंधन को देते हुए कहा कि नेट जीरो व न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह वाहन मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने अतीत का स्मरण कराते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश के शहरों में स्ट्रीट लाइटें बेतरतीब और हैलोजन आधारित थीं, जो न केवल ऊर्जा की अत्यधिक खपत करती थीं बल्कि उनके नीचे गन्दगी और बदबू के कारण खड़ा होना भी दूभर था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से सरकार ने भेदभाव रहित 24 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ पूरे शहर को एक जैसी दूधिया रोशनी से जगमगाने का संकल्प लिया और सूर्यवंशी प्रभु श्रीराम के अनुज लक्ष्मण जी की नगरी लक्ष्मणपुरी से इस अभियान को गति प्रदान की। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में ई0एस0एल0 के माध्यम से 16 लाख एल0ई0डी0 लाइट बदली गईं, जिससे आज उत्तर प्रदेश के शहर रात के अंधेरे में भी सुरक्षित और सुन्दर दिखाई देते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि विगत 09 वर्षों में स्वच्छता रैंकिंग के साथ-साथ यहाँ मेट्रो का सफल संचालन, सड़कों का चौड़ीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं ने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। आज लखनऊ केवल प्रशासनिक राजधानी ही नहीं, बल्कि डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग के नए हब और एक 'सेफ सिटी' के रूप में स्थापित हो चुका है, जहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर के माध्यम से सुरक्षा की पुख्ता निगरानी की जा रही है। अयोध्या की तर्ज पर अब लखनऊ को भी 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जहाँ प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत लाखों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गौरव के साथ उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश आज देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ लखनऊ सहित 07 प्रमुख शहरों में मेट्रो का शानदार संचालन हो रहा है और अब सिटी बस सेवा को भी पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस सेवा में बदलने का कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से लखनऊ में अशोक लेलैंड और टाटा जैसी इकाइयों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू होना प्रदेश में बढ़ते निवेश और भविष्य की स्वच्छ परिवहन व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के अन्तर्सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व कूड़े के कुप्रबन्धन के कारण प्रदेश इन्सेफेलाइटिस, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से त्रस्त था, जिससे उत्तर प्रदेश की छवि एक 'बीमारू राज्य' की बन गई थी। परन्तु आज प्रदेश ने उन बीमारियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर खुद को भारत की अर्थव्यवस्था के 'ग्रोथ इंजन' और देश की टॉप 03 अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है। उन्होंने स्वच्छता को समृद्धि का आधार बताते हुए कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी की पूजा से पूर्व हम घरों की सफाई करते हैं, उसी प्रकार शहर की स्वच्छता ही राज्य की समृद्धि का द्वार खोलती है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए शुरू किए गए ये नए वाहन स्वच्छता अभियान को प्रत्येक वॉर्ड के घर-घर तक पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि गोमती नदी के पुनरुद्धार और कुकरैल नदी को अतिक्रमण मुक्त कर वहां स्थापित 'सौमित्र वन' आज लखनऊ की नई पहचान बन चुका है। अंत में मुख्यमंत्री जी ने सभी नगर निकायों को निर्देशित किया कि वे तकनीकी और संसाधनों का बेहतर समन्वय कर उत्तर प्रदेश के शहरी जीवन को और अधिक सुगम, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के इस मिशन को पूरी गम्भीरता से आगे बढ़ाएं।

नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट (प्रथम चरण) के उद्घाटन की झलकियां